विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 11 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 6/ 2026

प्रति,

कलेक्टर
जिला–दुर्ग
छत्तीसगढ़

विषय :–विधानसभा प्रश्न क्रमांक 996 तारांकित द्वारा श्री रिकेश सेन, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 996 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 02.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 12 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 6/ 2026

प्रतिलिपि :–

खाद्य नियंत्रक, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय उच्च मुल्य दुकान में चावल के स्थान पर नकद भुगतान**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **996**) **श्रीरिकेश सेन**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड पर मिलने वाले चावल के स्थान पर राशि (नकद) दी जा रही है तथा हितग्राहियों के हिस्से का चावल अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने की कुल कितनी शिकायतें विभाग/प्रशासन को प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या जांच और दंडात्मक कार्रवाई की गई है? दुकानवार व शिकायतवार विवरण देवें। (ग) नियमों के विरुद्ध चावल के बदले नकद राशि देने तथा गरीबों के चावल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने वाले राशन दुकान संचालकों एवं इसमें संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है? (घ) भविष्य में पात्र हितग्राहियों को उनका पूरा राशन (चावल) पारदर्शी तरीके से मिले और इस प्रकार के अवैध विक्रय/भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसके लिए विभाग क्या ठोस एवं सुधारात्मक कदम उठा रहा है?

उत्तर :

Collector Durg